भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3218

जिसका उत्तर 21.12.2023को दिया जाना है

सार्वजनिक और निजी वित्तपोषित परियोजनाएं

3218. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन टोल मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां सरकारी और गैर-सरकारी वित्तपोषित परियोजनाओं पर व्यय की गई पूंजीगत लागत पूरी तरह वसूल कर ली गईहै;

(ख) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, कार्यरत ऐसे टोल मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी वित्तपोषित परियोजनाओं में रियायत-अवधि पूरी होने के बाद छूटप्राप्तकर्त्ताओं द्वारा बंद किए गए टोल-बूथों की राज्य-वार सूची क्या है; और

(घ) सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं में कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा पूंजीगत लागत की वसूली के बाद बंद किए गए टोल बूथों की सूची क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) देश में ऐसा कोई भी पथकर वाला राष्ट्रीय राजमार्ग (सार्वजनिक/निजी वित्त पोषित) नहीं है जिसकी पूंजीगत लागत पूरी तरह से वसूल हो गई हो। हालाँकि, देश में निजी वित्त पोषित पथकर सड़कों का विवरण जहां रियायती अवधि समाप्त हो गई इस प्रकार हैं:

i. छत्तीसगढ़ राज्य में NH-53 का रायपुर-दुर्ग खंड।

ii. महाराष्ट्र राज्य में NH-60 का नासिक फाटा-खेड खंड।

iii. गुजरात राज्य में NH-48 का वडोदरा-भरूच खंड।

iv. गुजरात राज्य में NH-48 का भरूच-सूरत खंड।

v. गुजरात राज्य में NH-08 का सूरत-दहिसर खंड।

vi. महाराष्ट्र राज्य में NH-48 का सतारा-कागल खंड।

vii. मध्य प्रदेश राज्य में NH-07 का कटनी बाईपास।

(ग) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार रियायत अवधि/पूंजीगत लागत की वसूली के पूरा होने के बाद उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****